

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (NRA)

प्रलिस के लयः

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (NRA), आर्थिक और पर्यावरण लेखा प्रणाली (SEEA), सतत् विकास लक्ष्य (SDG), सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (GASAB), CAG ।

मेन्स के लयः

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (NRA) - इसका महत्त्व, भारत की पहल और इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के नयितरक और महालेखा परीक्षक](#) ने कहा है कनिवंबर 2022 तक प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (NRA) पर रपिर्ट जारी की जाएगी ।

- यह ज़मिमेदार उपयोग की नगिरानी में मदद करने के लयि लेखा प्रणाली वकिसति करने का एक प्रयास है, जो स्थरिता की ओर ले जाएगा ।

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (NRA)

परचियः

- प्राकृतिक संसाधन लेखांकन आर्थिक गतविधियिों के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन करने की एक प्रक्रया है
- NRA की अवधारणा प्राकृतिक पर्यावरण के वभिन्न घटकों और देश की आर्थिक प्रगति के बीच घनषि्ट अंतःक्रया को समझने हेतु उभरी थी ।
- यह इस अवधारणा पर आधारति है किकिसी संसाधन का मापन उसके बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाता है ।

ऐतहासिक परदृश्यः

- NRA के लयि पहला कदम मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन), 1970 में तब उठाया गया जब आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गरिवट के बीच संबंधों पर पहली बार चर्चा की गई ।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापति ब्रंटलैंड आयोग ने वर्ष 1987 में पर्यावरण और आर्थिक गतविधियिों के बीच घनषि्ट संबंध के वचार को व्यक्त कया, जसिके बाद पर्यावरण लेखांकन एवं वर्ष 1992 में रयिो डी जनेरयिों में पृथ्वी शखिर सम्मेलन हुआ ।

NRA को बढ़ावा देने हेतु पहलः

वैश्विक स्तर पर पहलः

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का शीर्षक- "ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड; द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट" (25 सतिंबर, 2016) जसि 190 से अधिक देशों की मंजूरी मलिी, को प्राकृतिक संसाधन खातों की तैयारी की आवश्यकता है ।
 - भारत इस संकल्प का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है ।
- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2012 में [आर्थिक और पर्यावरण लेखा प्रणाली \(SEEA\)](#) को अपनाया । यह NRA के लयि नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ढाँचा है ।
 - ऑस्ट्रेलया, कनाडा, चीन, फ्रंस और जर्मनी जैसे लगभग 30 देशों ने पर्यावरण लेखांकन को अपनाने में वभिन्न डगिरी हासलि की है ।
- यूरोपीय संघ द्वारा [वतितपोषति पारस्थितिकि तंत्र सेवाओं \(NCAVES\) परयिोजना का प्राकृतिक पूंजी लेखा और मूल्यांकन](#), संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD), [संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम \(UNEP\)](#) तथा [जैवविधिता के सम्मेलन \(CBD\)](#) के सचवालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू कया गया है ।
 - भारत इस परयिोजना में भाग लेने वाले पाँच देशों में से एक है, अन्य देश बराज़ील, चीन, दक्षणि अफ्रीका और मैक्सिको हैं ।
 - यह प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक और प्रवाह को मापने एवं रपिर्ट करने के लयि व्यवस्थति तरीका प्रदान करने हेतु लेखांकन ढाँचे का

उपयोग करने के प्रयासों को कवर करने वाला व्यापक शब्द है।

■ **भारत-वशिष्ट पहल:**

- CAG ने वर्ष 2002 में सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (GASAB) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य नरिणय लेने की गुणवत्ता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिये सरकारी लेखांकन तथा वृत्तीय ररिपोर्टिंग के मानकों में सुधार करना था।
 - इसमें भारत सरकार में सभी लेखा सेवाओं के प्रतनिधि, RBI, ICAI और राज्य सरकारों जैसे नयिमक प्राधिकरण शामिल हैं।
- भारत का CAG प्रधान ऑडिट संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय नकिय का भी सदस्य है, जसि WGEA (पर्यावरण लेखा परीक्षा पर कार्य समूह) कहा जाता है, जसिने सुझाव दयिा (वर्ष 2010) कलिखा परीक्षा संस्थानों को अपने देशों को प्राकृतिक संसाधन लेखांकन को अपनाने में सहायता करनी चाहयि।

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन का महत्त्व:

■ **अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतरसंबंध:**

- पर्यावरणीय संसाधनों का लेखांकन गैर-नवीकरणीय क्षति की मात्रा नरिधारित करता है और वास्तविक रूप में विकास के नरिधारण में सहायता करता है।

■ **नीति नरिधारण में सहायता- सुदृढ डेटाबेस:**

- नीति नरिमाताओं को उनके नरिणयों के संभावित प्रभाव को समझने में मदद करना।

■ **सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) का प्रबंधन:**

- NRA **सतत् विकास लक्ष्यों** के साथ गहन रूप से अंतरसंबंधित हैं क्योंकि 17 में से 4 लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और उनके लेखांकन से संबंधित हैं।

■ **जलवायु परिवर्तन का सामना:**

- जलवायु परिवर्तन की नगिरानी, माप और वश्लेषण के लयि परसिंपत्तिएवं प्रवाह लेखा को एक उपयोगी ढाँचे के रूप में मान्यता दी गई है।

■ **अंतर्राष्ट्रीय प्रतबिद्धताएँ:**

- सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने के अलावा यह भारत को परसिंपत्तिलेखा के गठन में वशिष्ट देशों के समूह का हसिसा बनने में सहायता प्रदान करेगा।

प्राकृतिक संसाधनों के लेखांकन से संबंधित चुनौतियाँ:

- राज्य के अधिकारियों के उचित प्रशिक्षण और क्षमता नरिमाण का अभाव है।
- परसिंपत्तिलेखांकन के गठन में सीमाएँ- डेटा की आवधकितता का मानचरिण।
- संसाधनों के लयि डेटा संग्रह में कई एजेंसयिा शामिल हैं; यह डेटा साझाकरण/डेटा संघर्ष के मुद्दों को जन्म दे सकता है।

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड